Hindi / English (Bi-Lingual) Weekly Ghaziabad केन्द्र एवं उ०प्र० सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु मान्यता प्राप्त

of the Week लोकसभा चुनाव के तीसरे और सबसे बड़े चरण में 23 अप्रैल को 13 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 116 सीटों पर 66.07 प्रतिशत मतदान हुआ। कुल 302 सीटों पर मतदान के साथ चुनाव का आधे से ज्यादा सफर पूरा हो गया।

Inside Ghaziabad

पेज नबर 2 इंडियन एयर फोर्स की फर्जी पेज नबर 5

After failing to rape 70vear-old aunt...

IRUPATIEYE

डीएम ने किया स्ट्रांग क्तम का निरीक्षण

गाजियाबाद : जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने मंगलवार को गोविंदपुरम मंडी में बनाए गए स्ट्रांग रूम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण में जिलाधिकारी ने पाया कि स्रक्षा व्यवस्था में लगाए गए मजिस्ट्रेट, सिविल पुलिस व सीआइएसएफ के जवान स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात मिले। सीआइएसएफ के अधिकारी ने डीएम को जानकारी दी कि दिन में यहां पुलिस के दो उपनिरीक्षक, चार महिला कांस्टेबल व गार्ड तैनात रहते हैं। रात में दो उपनिरीक्षक, चार महिला कांस्टेबल व दो संतरी तैनात रहते हैं।

बाल संरक्षण कार्यों की समीक्षा होगी

गाजियाबादः जिले के दो गांवों में बाल संरक्षण के कार्यों की समीक्षा के लिए जिला प्रोबेशन विभाग की टीम जाएगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास चंद्र ने बताया कि इंद्रागढ़ी और निठौरा ग्राम पंचायत में बाल संरक्षण की स्थिति जानने टीम दो दिनों तक गांव में रहेगी।

एनआरएचएम घोटालों में हुई सुनवाई

गाजियाबाद : एनआरएचएम मामले में मंगलवार को सीबीआइ की विशेष अदालत में गवाही हुई। बिजनौर जिले के स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले में क्लर्क ब्रजमोहन सिंह की गवाही हुई। गवाह के रूप में उनका बयान कोर्ट में दर्ज किया गया। बिजनौर स्वास्थ्य विभाग में दवा खरीद में हुए घोटाले में सीबीआइ ने तत्कालीन सीएमओ डा. इंद्रपाल सिंह समेत अन्य आरोपित बनाए हैं।

स्वरथ रहना हैं तो लगाएं : दाधीरत भागेव

रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम गैलोर ने परमानंद वाटिका में लगाए पौधे

वसुंधरा : रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम गैलोर ने बुधवार को अर्थ—डे के मौके पर वसुंधरा सेक्टर-12 स्थित परमानंद वाटिका में आंवला, लेमन, पीच, नीम के दस पौधे लगाए। साथ ही इनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी ली। पौधारोपण कर रहे क्लब के चार्टर प्रेजीडेंट डा.धीरज भार्गव व मनीषा भार्गव ने कहा कि पृथ्वी को बचाना सभी का धर्म है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो पेड़ों की रक्षा करनी होगी। हम पृथ्वी का जन्म दिवस मना रहे हैं। हमारा उद्देश्य हरियाली को वापस लाना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम पेडों को बिना सोचे-समझे काट देते हैं। आज जंगलों को काट कर वहां इमारतें बन गई



हैं। पेड़ों की कमी से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे शुद्ध प्राण वायु मिलना मुश्किल हो रहा है। हम सिर्फ शहरों को स्मार्ट कर रहे हैं, गांवों पर ध्यान नहीं देते हैं। आज सभी नदियां प्रदूषित हो रही हैं, जिसका कारण हम सभी हैं। उन्होंने हरियाली बढ़ाने के लिए परमानंद वाटिका में आने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया।

पौधारोपण के साथ देखभाल भी जरूरी

डा.भार्गव ने कहा कि केवल पेड लगाना ही काफी नहीं है, बल्कि उनकी देखभाल करना भी बेहद जरूरी है। यदि सभी एक एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो कुछ हद तक हम प्रदूषण से मुक्ति पा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि आज हमें इस बात का भी ध्यान देना होगा कि कौन सा पौधा पर्यावरण के लिए जरूरी है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि लिपटस के पौधे न लगाएं। इससे जमीन को काफी नुकसान होता है।

शहरवासियों को मिलेगी 50 मीटर लंबे स्वीमिंग पूल की सुविधा

सुविधा मिलने जा रही है। स्वीमिंग पूल एक मई से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। खेल विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम में वर्ष 2013 में 50 मीटर लंबे और नौ मीटर गहरे स्वीमिंग पूल का निर्माण कराया गया था। खेल विभाग की ओर से हर वर्ष इसे शुरू करने की कोशिश की गई। तैराकी का कोच न होने की वजह से यह शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार शहारवासियों को इस स्वीमिंग पूल की सुविधा मिलेगी। शहरवासी अब गर्मी से

गाजियाबाद : शहरवासियों को राहत के लिए 50 मीटर लंबे महामाया स्टेडियम में बड़े (50) स्वीमिंग पूल में तैराकी कर सकेंगे। मीटर लंबे) स्वीमिंग पूल की खेल विभाग से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। स्वीमिंग पूल की सफाई कराई जा रही है। एक मई से लोग इसमें तैराकी कर सकेंगे। रजिस्द्रेशन की प्रक्रिया स्टेडियम में शुरू कर दी गई है। हालांकि स्टेडियम में पहले एक 20 मीटर लंबे स्वीमिंग पूल को चलाया जा रहा है। जिला क्रीड़ाधि ाकारी गदाधर बारीकी का कहना है कि महामाया स्टेडियम में बड़े स्वीमिंग पूल की शुरुआत एक मई से कर दी जाएगी। खेल विभाग स्वीमिंग पूल को तैयार करा रहा है। इसमें 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को एंट्री मिलेगी।

Private schools told submit fee details by April 29

directed all private schools in Gautam Budh Nagar to submit affidavits stating their current fee structure by April 29, failing which action will be taken. Fees can be revised by schools only after consultation with the administration, the district magistrate said. "Parents have been holding protests at different places against fee hike in schools. It's ideal for the school administrations to submit an affidavit stating their current

NOIDA: To check arbitrary fee structure. We'll initiate fee hike, the district action against schools that fail administration on Friday to furnish the details on time," BN Singh, the DM, said. In fact, a meeting between parents and the DM is also slated for Saturday. "Moreover, no school should charge increased fee without an approval from the appropriate authority as per the UP Self-Financed Independent Schools (Fee Regulation) Act 2018. We have received 10 complaints from parents about fee hike and are looking into them," he

इंडियन एयर फोर्स की फर्जी वेबसाइट बनाकर सैंकड़ों युवाओं से ठगी

www.tbcgzb.com

नई दिल्ली। इंडियन एयरफोर्स की फर्जी वेबसाइट बनाकर बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग का स्पेशल सेल की साइबर क्राइम युनिट ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस संबंध में राजस्थान निवासी दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान महेंद्र सिंह और विकास स्वामी के रूप में हुई है। दोनों ने राजस्थान के चुरू से बीसीए कर रखी है। आरोपियों ने देशभर के 400 युवाओं से उगी की है। स्पेशल सेल की साइबर क्राइम यूनिट के पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पिछले दिनों उनको इंडियन एयरफोर्स अधिकारियों की ओर से

शिकायत मिली थी। शिकायत में अधिकारियों ने बताया कि कुछ लोगों ने इंडियन एयरफोर्स की फजी वेबसाइट बनाकर उस पर नौकरी का विज्ञापन डाला हुआ है। युवा धोखा खाकर इस वेबसाइट पर नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। बाद में उनकी रकम को ऑनलाइन हड़प लिया जाता है। सूचना मिलते ही फौरन पुलिस अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। इस बीच कुछ शिकायतकर्ता भी पुलिस के संपर्क में आए। पुलिस ने फर्जी वेबसाइट के रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके लिंक किए हुए अकाउंट नंबर व मोबाइल नंबरों की जांच की।

विकास से जुड़े प्रोजेक्ट लेट होने पर डीएम सख्त

गाजियाबाद। शहर में विकास से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्टों की रफ्तार बढ़ने की जगह सुस्त पड़ गई है विकास प्रोजेक्ट की लेटलतीफी को गंभीरता से लेते हुए डीएम रितु माहेश्वरी ने जीडीए अधिकारियों की सोमवार को समीक्षा बैठक बुलाई है। जाम के झाम को खत्म के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्टों के पिछड़ने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। सबसे पहले दिल्ली—मेरठ हाइवे सीआरआरआई के ट्रैफिक मोबिलिटी प्लान के तहत 29 कटों को बंद करने के साथ कुल सात यू-टर्न का निर्माण होना है। यहां कई कटों को तो बंद कर दिया गया, लेकिन यू—टर्न का काम पिछड़ने पर डीएम नाराज हैं।

आप-कांग्रेस गठबंधन पर शीला ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- सभी सीट पर जीतेगी पार्टी

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन के अटकलीं पर चुप्पी साधी प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित ने सोमवार को अपना चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। मैं उत्तर-पूर्वी संसदीय क्षेत्र से निश्चित तौर पर जीत हासिल करूंगी। हमारा काम बोलता है। मैं स्वयं पूरे संसदीय क्षेत्र का दौरा करके मतदाताओं से मिलकर दिल्ली में कांग्रेस सरकार द्वारा 15 वर्षों के शासन काल की उपलि ायों के बारे में मतदाताओं को बताऊंगी। कांग्रेस पार्टी दिल्ली की सभी सातों लोकसभा सीटों पर पूर्ण बहुमत से बिना किसी रुकावट



के जीत दर्ज करेगी। दिल्ली का विकास इस बात का गवाह है कि दिल्ली का चहुंमुखी विकास कांग्रेस की दिल्ली सरकार ने ही किया है। इसका मुकाबला न आम आदमी पार्टी कर सकती है और न ही भाजपा। आम आदमी पार्टी का पिछला कार्यकाल झूट और फरेब पर आधारित रहा है। प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक के बाद जमकर समर्थन में नारेबाजी की ।

कोटद्वार व नजीबाबाद जाने वाली 18 बसें बंद

नोएडा। मोरना डिपो से कोटद्वार, नजीबाबाद और चांदपुर के लिए चलने वाली 18 बसों की सेवा कुछ दिन के लिए बंद करनी पड़ी है। यह सेवा बिजनौर में गंगा बैराज के क्षतिग्रस्त होने के कारण बंद हुई है। एआरएम अनुराग यादव ने बताया कि नोएडा डिपो से कोटद्वार के लिए 8 और आनंद विहार व कश्मीरी गेट से दो-दो बसें चलती हैं। इसके अलावा डिपो से नजीबाबाद के लिए पांच और चांदपुर के लिए एक बस चलती थी। बसों का रूट डायवर्ट इसलिए नहीं किया गया, चूंकि सीएनजी भरने के बाद बस केवल 270 किलोमीटर ही चल पाती हैं। अगर रूट डायवर्ट करके चलाई गईं तो रास्ते में ही सीएनजी खत्म हो जाएगी।

15 मई तक हिंडन एयरबेस से घरेलू उड़ान

गाजियाबाद। हिंडन एयरबेस से घरेलू उड़ान सेवा की जल्द ही उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोशिश में लगी है कि 15 मई तक उड़ान सेवा शुरू कर दी जाए। इसको लेकर अंतिम तौर पर रूटों का निर्धारण होना बाकी है, जिसको लेकर अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक अहम फैसला होने की संभावना है। उधर, टर्मिनल से जुड़ा अधिकांश काम पूरा कर लिया गया है। हवाई उड़ान सेवा को संचालित करने के लिए ट्रांसमिशन से लेकर अन्य सुविधाओं से सिकंदरपुर टर्मिनल को लैस कर कर दिया गया है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत 60 करोड़ रुपये की लागत से हिंडन एयरबेस से सटे सिकंदरपुर गांव में टर्मिनल बनाया गया है।



इसका उद्घाटन आठ मार्च को प्रध गानमंत्री की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन उस वक्त तक काम पूरा न होने के कारण उड़ान सेवा शुरू नहीं हो पाई थी। अब काम पूरा हो चुका है, बस उड़ान का इंतजार है। बताया जा रहा है कि 80 सीटर विमान सेवा शुरू करने के लिए हुबली, जामनगर, शिमला, कन्नूर, नासिक, फैजाबाद, पिथौरागढ़, गुलबर्गा तक उड़ान सेवा शुरू करने की योजना थी, लेकिन जेट एयरबेस की उडान सेवा बंद होने के बाद अब पहले चरण में कुछ रूट घटाए भी जा सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी

ऑफ इंडिया चाहती है कि दिल्ली एयरपोर्ट का दबाव कम करने के लिए घरेलू उड़ान सेवा की अधि ाकांश फ्लाई हिंडन एयरबेस पर संचालित हों। इसको लेकर निजी विमानन कंपनियों ने भी नवंबर 2017 में उस वक्त काफी दिलचस्पी दिखाई, जब पहली दफा हिंडन एयरबेस से उड़ान सेवा का प्रस्ताव आया था। प्री-फेब्रिकेटेड तकनीक पर निजी क्षेत्र की ईपैक पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने रिकार्ड चार महीने में सिकंदरपुर एयरपोर्ट को तैयार किया है। टर्मिनल के अंदर व्यस्त समय के अंदर एक घंटे के अंदर 300 यात्रियों को झेलने की क्षमता है जो पूरी तरह से एयर कंडीशन, एलईडी लाइट और डबल इंसुलेटेड रुफ सिस्टम से सुसज्जित है।

स्काउट एंड गाइड कैंप में शामिल हुए छात्र

गाजियाबाद : आध्यात्मिक नगर स्थित इंमैंटेक संस्थान में आयोजित पांच दिवसीय स्काउट एवं गाइड कैंप के चौथे दिन छात्रों ने विभिन्न गतिविधि ायों में भाग लिया। छात्रों ने अलग–अलग राज्यों से संबंधित कैंप लगाए। राज्यों से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए। समापन अवसर पर छात्र इन राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। इस मौके पर पंकज ए. गुप्ता, डा. लतिका गुप्ता, बीएड प्राचार्या डा. निधि अग्रवाल और जिला संगठन आयुक्त (स्काउट) श्याम सिंह मौजूद रहे। श्याम सिंह ने कैंप का संचालन किया। संस्थान के कार्यकारी निदेशक डा. पंकज ए. गुप्ता ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से छात्रों में समय की बचत करने की क्षमता उत्पन्न होती है।

हाथी की जगह गलती से दब गया कमल का बटन, बसपा समर्थक ने अफसोस में काट ली अपनी अंगुली

शिकारपुर : मतदान के दौरान जल्दबाजी में मनपसंद प्रत्याशी के स्थान पर भाजपा का बटन दबाने के बाद खुद को बसपा का समर्थक बताने वाले युवक ने अपनी तर्जनी अंगुली काट ली। परिजनों ने युवक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टर ने इलाज के बाद उसे घर भेज दिया। जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के गांव अब्दुल्लापुर ह्लासन निवासी पवन कुमार (24) बसपा का समर्थक है। गुरुवार को वोट डालने के लिए वह गांव रिथत मतदान केन्द्र पर गया था। मतदान के दौरान जल्दबाजी में उसने अपने मनपसंद प्रत्याशी



के निशान हाथी के बजाय कमल के निशान वाला बटन दबा दिया। पवन ने बताया कि वोट डालने के बाद वह आत्मग्लानि से भर गया। घर आकर गुस्से में उसने निशान वाली बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली का अगला हिस्सा धारदार हथियार से काट लिया। उसके चीखने चिल्लाने पर परिजन उसे अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसकी मरहम पट्टी की।

धांधली : विवाह पंजीकरण प्रक्रिया की सख्त

गाजियाबाद। फर्जी संस्था की आड में विवाह करना और घालमेल कर पंजीकृत कराने के मामले में शासन ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं। अब विवाह पजीकरण से जुड़ी प्रक्रिया को पहले के मुकाबले सख्त कर दिया गया है। अब विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण के वक्त तीन स्तर पर अभिलेख अपलोड करने होंगे। सबसे अहम बात ये है कि अब विवाह पंजीकरण के वक्त जन्म प्रमाण पत्र भी देना होगा। उसके लिए सिर्फ पांच अभिलेख ही मान्य होंगे। इसके साथ ही दंपति को विवाह पंजीकरण के वक्त अलग–अलग शपथ पत्र भी देना होगा। शासन के निर्देश पर पंजीकरण संबंधित सॉफ्टवेयर में भी नई व्यवस्था से जुड़े विकल्पों को भरना अनिवार्य कर दिया गया है। विवाह पंजीकरण के मामले में लगातार शासन को शिकायतें मिल रहीं थीं कि कुछ फर्जी संस्थाएं अवैध तरीके से विवाह करा रही हैं। गाजियाबाद में ही 10 से अधि ाक ऐसी संस्थाएं पकड़ी र्गइं थीं, जिनका गठन आर्य समाज के नाम पर हुआ। डीएम रितु माहेश्वरी ने कुछ महीने पहले सदर तहसील स्थिति स्टांप एवं निबंधन कार्यालय में एक मामले को पकड़ा था। मौके पर मिली युवती ने बताया था कि उसे एक अधिवक्ता ने भरोसा दिया है कि उनकी शादी पंजीकृत करा दी जाएगी। मामले में डीएम ने जांच कराई तो सब रजिस्ट्रार पंचम के दफ्तर में सबसे ज्यादा विवाह पंजीकृत पाए गए थे। जांच में यह भी सामने आया था कि शादी पंजीकरण कराने वाले अधि

ाकांश दंपति दूसरे राज्यों के हैं। कमेटी की जांच रिपोर्ट में थाना कविनगर में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी की तरफ से शासन को पत्र लिखकर सिफारिश की गई कि विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया में बदलाव किया जाए। उधर, शासन को आम जनमानस से भी विवाह पंजीकरण प्रक्रिया में खामियों को लेकर शिकायतें मिल रहीं थीं, जिसको देखते हुए कमेटी गठित की गई। अब उसकी कमेटी के सुझावों के आधार पर पंजीकरण प्रक्रिया में बदलाव कर पहले से सख्त बना दिया है। अब पंजीकरण के वक्त पहचान, पता, आयु प्रमाण पत्र संबंधी अभिलेख देने होंगे, जो सिर्फ सरकार की तरफ से निर्गत ही मान्य होंगे।



रैपिड रेल के लिए 399 करोड़ की सरकारी जमीन देगा शासन

मेरठ : दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने वर्षों पुराने नियमों को शिथिल कर सरकारी जमीन के बदले जमीन की जगह उसे पैसों में समायोजित करने की बात कही है। शासन के आदेश के तहत कुल 399 करोड़ की सरकारी जमीन रैपिड रेल के लिए दी जाएगी, इसके एवज में संबंधित विभाग को पैसे दिए जाएंगे। यह जानकारी रैपिड रेल से जुड़ी कंपनी एनसीआरटीसी के अधिकारियों ने प्रशासन को दी है। डीएम के निर्देश पर एडीएम (प्रशासन) रामचंद्र एनसीआरटीसी के मुख्य परियोजना प्रबंधक को पत्र भेजा था। पत्र में उन्होंने कहा था कि

एमएमजी और संयुक्त अस्पातल में रेबिज के इंजेक्शन खत्म

गाजियाबाद : शहर के सभी सरकारी अस्पतालों एंटी रेबीज इंजेक्शन खत्म हो गए हैं। एमएमजी और संयुक्त अस्पताल के साथ–साथ सीएचसी व पीएचसी में भी खत्म हो गए हैं इसके चलते मरीजों को निजी अस्पतालों में मोटी राशि खर्च करनी पड रही है। जिला एमएमजी अस्पताल में पिछले 10 दिनों से एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं हैं। इसके अलावा तीन दिन पहले संयुक्त अस्पताल में भी इंजेक्शन खत्म हो गए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार सीएचसी, पीएचसी और स्वास्थ्य केंद्रों पर भी एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं है।



प्रोजेक्ट के लिए ली जाने वाली जमीन में 3.092 हेक्टेयर जमीन ग्राम समाज और सार्वजनिक उपयोग की है। शासन की व्यवस्था के तहत सार्वजनिक उपयोग की जमीन के बदले उसके समतुल्य जमीन दिए जाने की व्यवस्था है। एनसीआरटीसी से प्रशासन ने सार्वजनिक उपयोग की जमीन के बदले जमीन उपलब्ध कराने का ब्योरा देने को कहा। इस पर एनसीआरटीसी के अधिकारियों

ने जानकारी दी है कि प्रदेश सरकार ने रैपिड रेल की कुल लागत 30 हजार 274 करोड में से 6048 करोड़ का सहयोग देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इसमें 4726 करोड़ की वित्तीय सहायता, 923 करोड़ की स्टेट जीएसटी की छूट और 399 करोड़ की सरकारी जमीन देने की व्यवस्था की गई है। यह भी जानकारी दी गई है कि नई मेट्रो नीति-2017 के तहत प्रोजेक्ट के लिए सरकारी जमीन, जो या तो रियायती दरों पर पट्टे पर या बिना ब्याज के अधीनस्थ ऋण के तौर पर उपलब्ध कराए जाने की बात है। इस तरह रैपिड रेल प्रोजेक्ट में तेजी से काम के लिए प्रदेश सरकार ने कुछ व्यवस्थाओं को शिथिल कर दिया है।

सफाई के दावों के बीच नगर आयुक्त को मिली गंदगी

ट्रांस हिंडन : टीएचए में नगरायुक्त दिनेश चंद्र ने सोमवार को सफाई व्यवस्था का हाल जाना। लिंक रोड पर गंदगी मिलने पर सफाई निरीक्षक को चेतावनी दी गई है। वहीं भूषण स्टील और रेडीसन ब्लू होटल के बाहर नाले पर स्लैब डालकर पार्किंग बनाने पर कार्रवाई के आदेश दिए। प्रह्लादगढ़ी में नगरायुक्त दिनेश चंद्र सोमवार की सुबह 8रू30 बजे पहुंच गए। मौके पर नगरायुक्त को लिंक रोड के वंदना, नंबरदार और ब्लैक स्टोन बैंक्वेट हॉल के बाहर कूड़-कचरा मिला। इस पर उन्होंने नियमानुसार कार्रवाई के अधिकारियों को निर्देश दिए।

वहीं भूषण स्टील और रेडीसन ब्लू होटल के बाहर नाले पर स्लैब डालकर अवैध तरीके से वाहनों के लिए पार्किंब बना रखी थी। इससे नाले की सफाई काम प्रभावित हो गया है। इस पर नगरायुक्त ने दोनों पर कार्रवाई के आदेश दिए। वहीं रेडीसन ब्लू होटल में कूड़े से कम्पोस्ट खाद बनाने की मशीन बंद मिली। मौके पर मशीन को संचालित करने वाले कर्मचारी भी नहीं मिले। इस पर नगरायुक्त ने नोटिस जारी कर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। वहीं वसुंधरा, मोहन नगर और सौर ऊर्जा की हरित पट्टी का भी निरीक्षण किया।

रिहायशी प्रुफ ने पासपोर्ट आवेदकों की बढ़ाई परेशानी

गाजियाबाद : पासपोर्ट आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए पांच साल तक रहने का प्रमाण देना भारी पड़ रहा है। इसी कारण हजारों की संख्या में पासपोर्ट आवेदन कार्यालय में लंबित हो गए हैं। रीजनल पासपोर्ट कार्यालय में 80 फीसदी मामले पुलिस का एडवर्स रिपोर्ट के आ रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि पुलिस आवेदकों से पिछले पांच साल कहां–कहां रहे इसका प्रमाण मांग रही है। गाजियाबाद रीजनल पासपोर्ट कार्यालय से 13 जिलों के लोगों के पासपोर्ट जारी किए जाती है। आवेदन करने के बाद पासपोर्ट कार्यालय आवेदक की पुलिस जांच के लिए विभाग के पास ऑनलाइन दस्तावेज भेज देता है। आवेदक के पते पर



पुलिस जांच करने पहुंचती है तो पता चलता है कि वह पिछसे दो या तीन साल से ही उस स्थान पर रह रहा है। जब पुलिस उससे पूछती है कि इससे पहले वह कहां रहे तो आवेदक दूसरा पता बताते हैं। पुलिस अपनी रिपोर्ट में यहीं लिखकर भेज रही है कि आवदेक दो या तीन साल से वर्तमान पते पर रहा है। इससे पूर्व के पते से इसका जांच करा ली जाए। इस रिपोर्ट को पासपोर्ट की भाषा में एडवर्स रिपोर्ट अवेदक जाता है। जब पासपोर्ट आवेदक

का पासपोर्ट नहीं पहुंचता तो वह कार्यालय आकर इसकी जानकारी करता है। जब उसके पता चलता है कि उसे पिछले पांच साल का रिकॉर्ड बताना है जहां-जहां वह रहा है। इसके बाद आवेदक एक पर्सनल पर्टीकुलर फार्म भरकर देता है। जिस पर वह पिछले पांच सालों में कहां–कहां रहा है उसकी जानकारी देता है। इसको पासपोर्ट विभाग फिर से पुलिस के पास भेज जाता है। यहां से रिपोर्ट जाने के बाद पुलिस संबंधित पतों की जांच करके वापस पासपोर्ट विभाग को रिपोर्ट भेजती है। जब जाकर आवदेक का पासपोर्ट बन पाता है। इस प्रक्रिया के चलते इन दिनों हजारों पासपोर्ट आवेदन विभाग में लंबित हैं।

एनजीटी ने मांगा जिलाधिकारी से जवाब

साहिबाबाद : अर्थला झील और पक्षी विहार की जमीन पर अवैध कब्जा होने पर एनजीटी ने नाराजगी जताई है। सोमवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हुई एक सुनवाई के दौरान गाजियाबाद जिलाधिकारी से वसुंधरा स्थित पक्षी विहार के तीन खसरे और अर्थला झील की जमीन पर अवैध निर्माण होने पर जवाब मांगा गया है। साथ ही यह भी पूछा गया है कि प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की गई। एनजीटी ने इसमें पुराने आदेशों का हवाला दिया है कि पक्षी विहार और अर्थला झील क्षेत्र के आसपास भारी मात्रा में अवैध ा निर्माण कैसे हो गया। इस पर जिलाधिकारी को अब तक की गई कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत करने को कहा गया है।

44 करोड़ में बनेगा चार्जिंग स्टेशन व बस स्टैंड

गाजियाबाद : शहर में प्रदूषण कम करने के लिए शुरू हो रही इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना एक और कदम आगे बढ़ गई। शासन ने बस स्टैंड और चार्जिंग स्टेशन का प्रस्ताव निगम प्रशासन से मांग लिया है। निगम डूंड़ाहेड़ा में पांच एकड जमीन देने को तैयार है। साथ ही निगम ने चार्जिंग स्टेशन और बस स्टैंड पर करीब 44 करोड़ रुपये खर्च आने का प्रस्ताव बनकर भेज दिया है। माना जा रहा है कि तीन से चार माह के अंदर 12 रूट पर बसें दौड़ने लगेगी। स्मार्ट इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत इन बसों को चलाया जाएगा। नगर विकास मंत्रालय के तहत यह बस सेवा शुरू होगी और इनकी फंडिंग प्रदेश सरकार करेगी। योजना पर काफी समय



से काम चल रहा है, लेकिन इस पर बात आगे नहीं बढ़ रही थी। जबिक मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री पूर्व में कई बार शहर में 100 बसें चलाने की घोषणा कर चुके। शासन स्तर से इलेक्ट्रिक बस चलाने का इसलिए भी जोर दिया जा रहा है क्योंकि शहर में वायु प्रदूषण से बुरा हाल है। डीजल और पेट्रोल वाहन से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने गाजियाबाद में 100 इलेक्ट्रिक बस चलाने का निर्णय लिया था। इसी सिलसिले में पिछले दिनों पहले लखनऊ में एक बैठक हुई। इसमें फंडिंग, बस स्टैंड और चार्जिंग सेंटर पर आने वाले खर्च तथा जमीन को लेकर चर्चा की गई। साथ ही निगम और परिहवन विभाग से जानकारा मागा गइ। शासन न बसों को जल्दी सड़कों पर उतारा जा सके इसके लिए निगम प्रशासन से प्रस्ताव मांगा था। इस प्रोजेक्ट के लिए निगम पांच एकड़ जमीन देने के लिए तैयार है। साथ ही एक प्रस्ताव भी भेजा है। इसमें बताया कि बस स्टैंड और चार्जिंग सेंटर पर 44 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बसों को चलाने के लिए पहले पांच रूट निर्धारित किए गए थे, लेकिन बाद में रूट की संख्या 12 कर दी गई थी। विद्युत एक्सईएन एवं प्रोजेक्ट प्रभारी मनोज प्रभात का कहना है कि शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है।

नगर निगम ने फॉगिंग के लिए 100 छोटी मशीन खरीदी

गाजियाबाद : नगर निगम ने फॉगिंग के लिए छोटी 100 मशीनें खरीद ली हैं। इनसे संकरी गलियों में भी आसानी से फॉगिंग हो सकेगी। 100 वार्डी के अंदर फॉगिंग होने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।निगम अभी तक बडी मशीनों से ही शर की मुख्य सड़कों पर फॉगिंग करा रहा था। वार्डों में इन मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, जबिक मच्छरों के प्रकोप से लोगों का बुरा हाल था। लोग लगातार वार्डों में फॉगिंग कराने की मांग कर रहे थे। नगर निगम ने अब वार्डों में फॉगिंग कराने के लिए छोटी मशीनें खरीद ली है। एक वार्ड में एक मशीन से रोज फॉगिंग होगी। इन मशीनों से फायदा

होगा कि यह संकरी गलियों तक आसानी से पहंच जाएगी। इन्हें साइकिल, रिक्शा या स्कूटर पर रखकर छाटा गोलया तक ल जाया जा सकता है। निगम प्रशासन ने मच्छरों के प्रकोप को देखते हुए शेड्यूल जारी कर रखा है। उम्मीद है कि छोटी मशीनों से फॉगिंग के बाद मच्छरों के प्रकोप से राहत मिल सकेगी। नगर आयुक्त दिनेश चंद सिंह का कहना है कि मच्छरों को मारने के लिए नियमित रूप से फॉगिंग हो रही हैं। छोटी मशीन खरीदने के बाद अब वार्डीं में फॉगिंग शुरू करा दी है। जोन के हिसाब से मच्छरों को मारने के लिए शेड्यूल जारी किया गया है।

www.tbegzb.com TIRUPATI BALAJI CHRONICLE

EDITORIAL

NYAY's impact could be much wider than expected

Congress president Rahul Gandhi and other leaders have been talking about NYAY being a policy to re-monetise the economy. Giving Rs 72000 per year to India's poorest 20% households under the Nyuntam Aay Yojana (NYAY) is the biggest poll promise of the Congress in these elections. The party has been peddling two kinds of justifications for it. First, the scheme has been described as some sort of last-mile assault on poverty in India. The country does not have updated poverty numbers after 2011-12. It is likely that the new poverty ratio will not be far from the 20% mark. So theoretically, NYAY can lead to complete eradication of poverty. This, however, is like keeping a patient alive on life support, and not comparable to poverty eradication through sustained income opportunities.

The second justification, and this has gained more traction recently, is to sell NYAY as a stimulus to the economy, which has been subject to deflationary shocks through policies such as demonetisation. Congress president Rahul Gandhi and other leaders have been talking about NYAY being a policy to re-monetise the economy. In principle, there is nothing wrong with this. Counter cyclical measures are an integral part of economic policy choices. But what the Congress does not seem to realise is that even if it is elected, a full-scale implementation of NYAY will come a good four to five years after demonetisation was rolled out. In other words, it's utility as an antidote to the liquidity squeeze, which demonetisation created, will be almost negligible. This brings up the question whether the party has a long-term vision about what it wants to achieve with NYAY. For example, sustained payments of Rs 72,000 year to the poorest (who are more likely to be from socially deprived groups) could fundamentally alter the socioeconomic balance of power in villages. It would not be a bad thing per se but it will cause significant disruption in the short to medium term. Such payments can also lead to enhanced demand for commodities such as pulses, which if not handled properly can lead to high inflation.

The short point is a scheme of NYAY's magnitude and design will have a much wider impact than just bringing back liquidity in the economy through purchases by the poorest. Many of these could significantly alter fault lines between the poorest and the not-so poor, rather than the richest. Inability to appreciate similar dynamics played a role in the economic headwinds, which the UPA 2 faced after its dream run in the first term.

-By Dr. Dheeraj Kumar Bhargava

Design ready for Delhi-Noida flyover, IIT approval awaited

NOIDA: The design for the 5.5km six-lane elevated road that is to come up from Chilla regulator area in Mayur Vihar Phase 1 and go on to Mahamaya flyover on Noida Expressway along the Shahdara drain is now ready. The UP State Bridge

Corporation, which got the design done by a Mumbai-based consulting firm, has sent the same to IIT-Delhi for approval and it is expected back next week, following which the Noida Authority will start the construction work, officials said.

'अर्श से फर्श पर' जेट एयरवेज

'रंक से राजा' बनने की कहानियां तो अक्सर ही सुनाई जाती हैं परंतु उनसे महत्वपूर्ण तथा आवश्यक 'अर्श से फर्श' पर गिरने की त्रासदीपूर्ण कहानियां हैं। इनमें सर्वाधि ाक महत्वपूर्ण अथवा प्रेरणादायक शायद वे हैं जहां कर्मठता विनाश से बचा लेती है। महीने भर में जैट एयरवेज एक त्रासदी बन गई जिसने 20 हजार कर्मचारियों को बेरोजगार किया तथा हजारों परिवारों की कमाई का जरिया छीन लिया। सस्ती उडानों वाली स्पाइस जैट ने शुक्रवार को कहा कि उसने जैट के 100 पायलटों सहित 500 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी दी है और वह नए हवाई जहाजों के साथ नए मार्गों पर अपनी सेवाएं शुरू करेगा, परन्तु यह किसी बड़ी और पुरानी एयरवेज को बचाने का समाधान नहीं हो सकता। परंतु जैट एयरवेज कोई अकेली नहीं है। 1981 से अब तक भारत में अपना कारोबार बंद करने वाली यह पांचवीं विमानन सेवा है। इससे पहले अन्य लग्जरी विमानन कम्पनी किंगफिशर के साथ ऐसा हुआ था। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि क्यों यह आपदा बस आने का इंतजार कर रही थी। सलाहकार कम्पनी के.

पी.एम.जी. के अनुसार साल 2020 तक भारत तीसरा तथा 2030 तक पहला बड़ा विमानन केन्द्र होगा। जहां तक आंकड़ों का सवाल है भारतीय विमानन बाजार में सब ठीक प्रतीत होता है। हवाई अड्डे यात्रियों से खचाखच भरे हैं। गत वर्ष 13.8 करोड़ यात्रियों ने उड़ान भरी जिनकी संख्या 2010 में केवल 5.1 करोड़ थी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में तीव्र वृद्धि हुई है। वक्त की पाबंदी बेहतर हुई है। 600 से अधिक विमान सेवा में हैं तथा 859 को शामिल करने की योजना है। फिर भी देश की सबसे पुरानी निजी एयरलाइन्स जैट एयरवेज अतिरिक्त फंड्क्षडग का इंतजाम न हो पाने के बाद अंततरू बंद हो गई। जैट एयरलाइन्स लगभग 1000 घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय मार्गी पर 115 विमान उड़ाया करती थी। कुछ वर्ष पूर्व घरेलू लीडर का पद सस्ती उड़ानें संचालित करने वाली इंडिगो एयरलाइन्स ने इससे छीन लिया था, फिर भी विमानन बाजार के सबसे अधिक 12 प्रतिशत हिस्से पर इसका ही कब्जा था। उसके पास मूल्यवान अनवरत विमान उडान कार्यक्रम और प्राइम एयरपोर्ट स्लॉट थे।

सबसे मुनाफे वाले अंतर्राष्ट्रीय मार्गी पर भी इसका ही कब्जा था। इसके बावजूद विमानन सेवा एक बिलियन डालर से अधिक के ऋण, जैट एयरवेज में 24 प्रतिशत हिस्सेदारी वाली ऐतिहाद एयरवेज के साथ इसकी सांझेदारी बिखर रही थी। ऐसा क्यों हुआ, इसका पहला कारण गत वर्ष विमान ईंध ान की कीमतों में वृद्धि और रुपए के अवमूल्यन से इसका खर्च बढ़ जाना था। अब यह कहा जा रहा है कि कम्पनी के वित्तीय स्वास्थ्य पर पिछले कुछ समय से प्रश्रचिन्ह लगा हुआ था और इसके ऑडिट भी नहीं किए गए थे। वास्तव में अब नरेश गोयल के निजी अकाऊंटों के फॉरेंसिक ऑडिट की बड़े जोरों से मांग की जा रही है। इसके पश्चात गोयल की ओर से समय और खरीददार रहते कम्पनी को न बेचने का निर्णय एक दूसरा कारण था और भी अधिक महत्वपूर्ण विभिन्न बैंकों द्वारा (मुख्य रूप से स्टेट बैंक) ऋण दिए जाने पर प्रश्न उटाए जा रहे हैं कि आखिरकार एक घाटा उठा रही कम्पनी पर क्यों और किस प्रकार ऋणों की बरसात होती रही जिसकी जांच अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए।

Truck uproots pole, colony in darkness for 12 hours

NOIDA: Over 200 houses in Hindon Vihar colony faced a 12-hour power shutdown after a truck crashed into an electric pole and uprooted it on Friday afternoon. Officials in the electricity department said there was a loss of Rs 1 lakh because of the collision. The accused driver has been identified as Monu (32), an original resident of Bihar who works with an export company. "The accident took place around 2.45pm on Friday. It caused massive sparks in the overhead wires. People living in the neighbourhood rushed out of their houses after hearing

the sound of the collision," a local resident said. Bitto Kumar, another resident, said the driver appeared to be drunk. "We suspect he lost control of the vehicle at the sharp turn near the colony and crashed into the concrete electricity pole. The speed of the truck would be around 50kmph, quite high considering that the area is quite crowded. After the pole was uprooted, there was outage in the whole area," he said. With the mercury rising, most of the families had to spend the evening sitting outside or on the roof, waiting for power to

3 cars, 2 men, 1 method leave cops guessing

NOIDA: They come in a blue Baleno, a grey Santro or a red i10, knock on the windows of cars they intend to target and loot passengers at gunpoint when they roll down the glasses. Two men — one well-built and the other frail — are giving both commuters and police in Noida sleepless nights. Their sketches have been drawn, but they don't match the images of any wellknown criminal in the city. The cops were close to nabbing them twice, but the duo managed to speed away in the darkness. The gang has been presumed to be behind three dozen robberies across Noida city and Surajpur.

Body of boy who fell in to Noida drain recovered

NOIDA: The body of a sixyear-old boy, who fell into a drain in Noida on Monday, was recovered Tuesday morning, an NDRF official said. The body was recovered at 8:45 am, hours after a joint search by the Noida Police and the National Disaster Response Force (NDRF). The boy fell into the drain on Monday afternoon when he along with some other children was crossing the drain near Salarpur Khadar village, police said. The child, identified as Class 1 student Saurabh, lived with his family in a village in

Sector 81. "The body was recovered around 8.45 am. It was found about 1,500 metres down the stream from the incident site where water flow had slowed down," NDRF official Jitendra Kumar Yadav, who oversaw the operation, told PTI.

After failing to rape 70-year-old aunt, 37-year-old slits her throat

GHAZIABAD: A 37-year-old man has been arrested for allegedly killing his septuagenarian aunt on Tuesday night in Modinagar, police said on Sunday. Police said Rajbir had entered the house of 70-year-old Savitri Devi in Sikri Kalan village in an inebriated state with an intention to sexually assault her. When she raised an alarm, the accused slit her throat and wrists with a pocketknife. Devi was found dead in a pool of blood by her neighbours on Wednesday morning, the cops said. They initially suspected robbery but ruled it out after

conducted a probe and found his mobile phone's location in the area at the time of the incident. SP (rural) Neeraj Kumar Jadaun said, "Around 11pm on Tuesday, Rajbir jumped inside the woman's house while she was asleep. She immediately woke up and started abusing him. The accused then took a knife, which was lying nearby and attacked the woman." After the murder, Rajbir spent the night at Modinagar railway station.

jewellery and cash were found

inside the house. The residents

raised suspicion over Rajbir,

following which the police

2 killed in clash between cattle thieves, villagers in Greater Noida

GREATER NOIDA: Two persons were killed after a clash between cattle thieves and villagers in Jarcha early Sunday morning. Police said a group of thieves ambushed a cattle shed in Khurshidpura village in the morning and tried to steal some buffaloes. "The cattle owners woke up and raised an alarm. The thieves opened fire in which a local Ratan Singh (59) was injured. He was rushed to a private hospital where he succumbed to injuries," said Jarcha police.

Woman refuses money, son kills her with a brick

GHAZIABAD: A 40-year old man was arrested on Friday for allegedly killing his 65-year-old mother in Masuri four days ago. The woman's body was found with head injuries in a forested area on April 15 after she reportedly went missing from her farmland earlier that day. Police said the arrested man, Bhagat Singh, had asked for Rs 1 lakh from his mother Ramrati for renovating his house but she refused to give the money. In a fit of rage, Singh hit his mother with a brick several times while she was resting in the fields. Later, he dumped the body in a

nearby jungle. In the evening, he spread the news that his mother had been missing since afternoon. Singh joined his two younger brothers in a search operation and took them to the place where the body was lying. The three brothers brought the body home and on the insistence of villagers, informed the police. Initially, Singh tried to perform the last rites without informing the police. Later, the recovery of the brick and a blood-stained shirt from the crime scene raised suspicion among the cops.

Will build flats in 3 years, says Jaypee; buyers not sure

NOIDA: Only 200 Jaypee homebuyers attended a meeting that the company's former CMD Manoj Gaur had called on Friday to discuss the delay in delivery of 22,000 flats. Of them, 50 investors staged a hunger strike outside the venue. At the meeting, Gaur assured completion of Wish Town projects within three years and offered to put Rs 1,500 crore in an escrow account, to be monitored by a retired SC judge-led committee, for completing the flats. But the buyers were not convinced, and said "at least Rs 12,000 crore is required for the same".

9 months after cave-in, crater still gaping in Ghaziabad

GHAZIABAD: Nine months after torrential rains triggered a massive cave-in at Vasundhara Sector 4C leaving a crater about 30ft deep and 20ft wide next to two residential societies, Vartalok and Pragya Kunj apartments — neither has the crater been filled nor the road rebuilt. With monsoon just a few months away, residents of the two affected housing societies are now fearing the worst. The cave-in, that happened in July 2018, led to a major scare for the 90-odd families in the two apartment blocks. The crater had left the boundary walls of the apartments dangling in air, and the families were

temporarily evacuated. Government agencies and authorities scrambled to control the damage, closing down the road that had caved in, and vowing to fill a trench, allegedly dug by the builder. "The authorities and departments showed tremendous alacrity after the cave-in, but ended up with some band-aid solution like filing the crater with sandbags and debris, and even closing down the road for a while," said Rajeev Kumar, RWA president, Vartalok Apartment. "Just when we began believing the authorities would execute a permanent solution, they left midway. The trench is still not filled and the affected patch of road temporally filled with construction debris," added Kumar. Residents appealed to UP Housing Board, which administers Vasundhara, but their pleas fell on deaf ears. "Apart from writing to officials, I've also written to the district magistrate several times and lodged a complaint on the Jan Sunvai portal, but there's no movement thus far," he said. Bhola Singh, the executive engineer of the Housing Board, said cost estimates for filling the trench and rebuilding the road have been sent to the state government.

Rs 10 lakh stolen from temple donation box

NOIDA: Agitated over the alleged theft of Rs 10 lakh from donation boxes at Beri Wala Temple, residents of four villages gathered outside Expressway police station on Wednesday and demanded action. According to the villagers, around 15 days back, a Ramkatha recital was held at the temple when the head priest Anandsharan Maharaj asked his subordinates to take out money from the donation box for making arrangements. However, on checking, the five donation boxes were found empty. Subsequently, another priest Sachidanand baba, was called to the temple but he did not appear in front of the head priest.

Cattle thief, farmer killed in exchange of fire in Greater Noida

GREATER NOIDA: A suspected cattle thief and a farmer died in an exchange of fire in a village in Greater Noida's Jarcha area early on Sunday. While the villagers of Khurshidpura claimed that the two were hit by bullets that the thief's accomplices had fired to scare them away, police have not ruled out the role of any local resident in shooting the thief dead. Two accomplices tried to take away the slain thief's body, but failed. As the villagers gave them a chase, they escaped in the darkness. Till late on Sunday evening, the identity of the slain thief was

yet to be established. Police said they had registered a case and were investigating the matter. A sub-inspector at Jarcha police station, Subhash Chandra, was suspended as the villagers alleged that the police responded around two hours late. Police attributed the delay to lack of personnel, saying much of the force had been dispatched to different districts for the Lok Sabha polls. Khurshidpura village, 25km from Pari Chowk, is home to around 3,000 people. The villagers are mostly involved in farming and a few own cattle for their agricultural needs.

Noida spent Rs 2 crore on shelters for cattle, but they're still on the streets

NOIDA: An RTI response has revealed that Noida Authority spent Rs 2 crore in the last financial year for the upkeep of stray cattle in the city, yet most can be seen roaming on roads, posing traffic hazard. "I had filed an RTI query in January this year with the Noida Authority, asking how much they had spent in the past five years. So far, I have got only one response from Noida's public health department, which had spent Rs 2 crore on stray cattle in the last financial year.

Deputy SP's assets found to be 3 times his income, booked

GHAZIABAD: A deputy superintendent of police (DSP) posted with the UP Provincial Armed Constabulary (PAC) in Ghaziabad has been booked for allegedly possessing assets disproportionate to his income from known sources. DSP Ashok Kumar (55), a resident of Sector 9, New Vijay Nagar, posted as assistant commander of the 47th battalion of PAC in Ghaziabad. Shlok Kumar, SP (City), said an FIR was lodged against Ashok Kumar under sections 13.1A (criminal misconduct by public servant) and 13.2 (punishment for criminal misconduct by public

servant) of the Prevention of Corruption Act at Vijay Nagar police station on Thursday. "The FIR was lodged after after an investigation by the anticorruption bureau (ACB), Meerut. The report was first sent to the DGP office in Lucknow, which ordered Ghaziabad police to lodge an FIR against him," the SP added. As per the report, Ashok Kumar's total income between January 1, 2004, and December 31, 2012, was Rs 47.49 lakh. But the assets owned by him and his family during that period amounted to Rs 1.43 crore, more than three times the income.

डीएम

आवास –

एडीएम (सिटी)

एडीएम (प्रशासन) –

पासपोर्ट कार्यालय—

सिटी मजिस्ट्रेट –

आयकर विभाग-

हेल्प लाईन नंबर

गाजियाबाद प्रशासन

पुलिस अधिकारी

एसएसपी —2820758,9643322900

पुलिस अधीक्षक नगर—2854015

पॅलिसअधी. यातायात—2829520

2824416

2820106

2828411

2827016

2827365

2714144

2721779



Ghaziabad stretch of Delhi-Meerut RRTS likely to be operational by 2023

GHAZIABAD: A segment of the Delhi-Ghaziabad-Meerut Regional Rapid Transit System (RRTS) corridor, from Sahibabad to Duhai, is likely to become operational by March 2023. The National Capital Regional Transport Corporation (NCRTC) is working on a plan to achieve the target. The deadline for the entire corridor Sarai Kale Khan to Meerut is March 2024. Officials said the Uttar Pradesh chief secretary is likely to hold a meeting with all stakeholders, including the Ghaziabad Development Authority and Meerut Development Authority, on April 29 to discuss the project. "There

are three levels of monitoring or coordination committees that have been constituted to ensure that work on the proposed RRTS corridor happens without any impediment and the UP chief secretary, in the capacity of the convener of one such committee, has convened a meeting that is likely to take place on April 29," said an official. "This is to ensure that all problems coming in the way of the corridor are addressed and solved without delays. The government wants the first RRTS train operation on the 17km route between Sahibabad and Duhai to start by March 2023. The deadline (for the entire stretch) is 2024," the official added. Talking about the progress of the project, he said for the 17km stretch, works like road widening, tree cutting, geotechnical investigation, detailed designing and appointing consultant for station design are on. Civil work on the stretch will be taken up in two phases and the contract will be awarded soon, said the official. AGDA official said NCRTC needs land near Hindon Motel through which the proposed corridor will pass. "We have apprised the Meerut divisional commissioner of the NCRTC's request. Apart from that, a request for 8.5 acres near the elevated road at Vasundhara has been made by the NCRTC, which it plans to use for casting yard. It is being looked into," said VN Singh, the chief engineer, GDA. The 82 km Delhi-Ghaziabad-Meerut RRTS corridor, from Sarai Kale Khan in Delhi to Modipuram in Meerut, will have four stations in Ghaziabad — Sahibabad, Ghaziabad, Guldhar and Duhai. The cost of the entire corridor has been pegged at Rs 3,0724 crore out of which, the UP government's share will be Rs 6,500 crore. Once completed, trains with an average speed of 100kmph will cover the 82km distance in 55 minutes.

सीओ प्रथम– 2733070 सीओ द्वितीय – 2791769 सीओ एलआईयू— 2700925 सीओ लोनी– 3125539 जीडीए

उपाध्यक्ष जीडीए – 2791114 जीडीए सचिव – 2790891

अस्पताल

सी.एम.ओ. – 2710754 सी.एम.एस. 2730038 आपातकालीन – 2850124 कोलम्बिया एशिया —3989896 यशोदा अस्पताल—2750001—04 गणेश अस्पताल –4183900 संतोष अस्पताल –2741777 सर्वोदय अस्पताल —2701694 नरेन्द्र मोहन अस्पताल 2735253 जिला अस्पताल(एम्बुलेंस) 2730038

यशोदा अस्पताल (एम्बुलेंस) 2701695

पृष्पांजली क्रांसले हॉस्पिटल 4188000

पृष्पांजली मेडिकल सेन्टर 43075600

बीएसएनएल

आदेश कुमार (जीएम) 2755777

अग्निशमन विभाग

नगर कन्ट्रोल कोतवाली 2732099 जिला कन्ट्रोल रूम –2766898

पुलिस स्टेशन

एसएचओ इंदिरापुरम–संदीप कुमार सिंह-9643322921 एसएचओ लिंक रोड— लक्ष्मी सिंह चौहान-9643322924 एसएचओ—साहिबाबाद– जितेंद्र कुमार सिंह– 9643322923 एसएचओ खोडा– सतेंद्र 9643322922 प्रकाश– कोतवाली 2732088 सिहानी गेट 2791627 कविनगर – 2711843 विजयनगर — 2740797 इंदिरापुरम 2902858 लोनी – 2600097 अग्निशमन विभाग -27320999818702101

रेलवे इन्कवायरी -131

नगर निगम

नगरायुक्त— 2790425,2713580

विद्युत विभाग

मुख्य अभियंता – 2821025

पूछताछ

रेलवे कस्टमर -2797840, 139 रिजर्वेशन 8888 रोडवेज इन्कवायरी -2791102

प्रेस विज्ञप्ति, समाचार, विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें। **Phone No.:** 0120-2850800, 2850297

Online nod for building layouts likely in June

GHAZIABAD: The Uttar Pradesh government is planning to introduce by June 23 a system to approve building plans online. It is working on a software that will approve or reject building plans uploaded online within hours. Now, it usually takes anything between two and 30 days to get layouts approved. "Currently, development authorities have to rely on manual and traditional methods for approving maps. Building plans are now examined by the officials concerned to check if they conform to the existing bylaws or land use," said Ishtiaq Ahmed, chief architect and

town planner at GDA. "These officials have to check physically if all the departments have given their NOCs. This, obviously, takes a lot of time," he added. Sources said the software would have all the bylaws embedded into the system and would check for violations, if any, when a map is uploaded online. The sources refused to divulge details on how the system would work, saying it was still in a nascent stage. "As of now, online approvals are carried out by the GDA. But such approvals are limited, only for 'low-risk' properties," said Ahmed.

Private firm executive found hanging in Ghaziabad highrise

GHAZIABAD: A47-year-old man was found hanging from the ceiling fan at his home in Shipra Sun City, a highrise housing society in Indirapuram, on Monday. Police said that no suicide note had been found. According to the police, the deceased, identified as Ajit Pratap Singh, had been working as a director with a private business development company. Earlier, he worked as marketing head in private news channels. Pratap's body was spotted when his domestic help arrived on Monday afternoon. Sandeep Kumar Singh, SHO of Indirapuram police station, told

TBC that the woman had a duplicate key to the third-floor flat and she raised the alarm after she saw the body. The woman, Sakuntala, also informed the neighbours and the security guards of the society. Sakuntala said she had reached Pratap's house around 2pm and when she entered his bedroom to clean it, she saw him hanging from the ceiling fan. "On Sunday, he looked happy. Why he did this is a mystery," she said. The SHO said: "The police got information at around 2.20pm on Monday and a team reached the spot.

GMC says it has excess water but grapples to meet demand

GHAZIABAD: Water crisis in Ghaziabad Municipal Corporation (GMC) area is likely to worsen this summer, as the civic body grapples to bridge the gap between residents' demand and its own supply. The GMC has 337 MLD (million litres per day) of water, when demand in the civic area is 328 MLD. But on the ground, the civic body supplies only 256 MLD to the residents. The rest —72 MLD—is lost to leakages and other factors. "Non-revenue water accounts for 24% of the total water produced, which we lose to leakage and other deficiencies in the existing infrastructure. As a result, although we produce water in excess to the demand, we can supply far less than what residents need," said BK Singh, the general manager, water works department, GMC. The civic area has a population of 19 lakh and despite a 2,547-km pipeline, 22% residents face water shortage. Sahibabad and Vijaynagar are two of the most affected areas. Of the 337 MLD the GMC gets, 93 MLD is from Gangajal water supply project, which mostly caters to Vasundhara zone and delta colonies like Surya Vihar. The civic body gets 244 MLD by extracting groundwater, which it stores in 67 overhead tanks. The

GMC has also 24 underground water reservoirs at its disposal. During summer, the crisis worsens, as the groundwater level goes down and boring becomes difficult. "Of the 6,982 hand pumps in the civic area, 569 are defunct because the water table has gone down and there is an urgent need of re-boring," Singh said. The GMC has identified 20 spots where deep tubewell re-boring is required. According to an official, the average water table in the city is between 120 and 130 feet. Five years ago, it was at 100 feet. This time, many residents might have to depend on packaged water to fulfil their

potable needs. A resident of Kavinagar, TP Tyagi, said to deal with water shortage, the GMC should lay stress on the Gangajal project. "There is nothing one can do about the receding groundwater level as such. The water is also contaminated. The best option available (to procure more water) is the Gangajal project ," he said. Asked about plans the civic body has to strengthen its water infrastructure, an official said there are plans to invest Rs 30 crore on laying pipelines under AMRUT scheme. The Prime MInister had inaugurated the project in March.

Mother, brother kill girl, dump body in sack

GHAZIABAD: A 15-year-old girl was on Thursday allegedly killed by her mother and brother and her body stuffed in a sack in Loni's Sangam Vihar colony. Police arrested the duo after being alerted by the locals. The deceased girl, identified as Khushi Kumari, hailed from Mansurpur area of Muzaffarnagar district, said police. She was living in a rented accommodation in Sangam Vihar colony of Ghaziabad along with her mother and elder brother, who is a minor. According to police, on Thursday around 2.30pm, following a dispute, Khushi was strangled to

death by the mother-son duo, who then stuffed her body in a sack. Neighbours spotted the two trying to take the body on a scooter to an isolated place for dumping and informed police. The duo was arrested around 4 pm. "Both the accused were caught redhanded while they were taking the girl's body, which was stuffed in a sack, on a Scooty. The neighbours suspected something fishy and intercepted them, upon which they found the girl's body and immediately informed police," Neeraj Kumar Jadaun, superintendent of police (rural), told TBC.

Youth shot dead for liquor protest

GHAZIABAD: A 24-year-old man was shot dead in Modinagar on Wednesday. The deceased, Dipendra, was from Krishna Kunj area. The crime took place around 5 pm when Dipendra was in the house of his friend Vicky Tyagi on Tibra road. Five men allegedly barged into the house and fired 12 bullets. Six of those hit Dipendra. He was taken to a nearby private hospital, where he was declared brought dead. Sources said there was tension in the area after a liquor shop opened. Women opposed it and Dipendra was on their side.

70-year-old woman living alone at home found with throat slit

GHAZIABAD: The body of a 70-year-old woman with her throat and wrists slit was found at her home in Ghaziabad's Modinagar on Wednesday morning. Local people said the woman, Savitri Devi, had been living all by herself in the singleroom house at Sikri Kalan village for almost three decades, ever since her husband's death. She used to work as a domestic help. On Wednesday, when the woman did not answer repeated knocks on her door, some of her neighbours looked through

the roof of the house and found her lying on a wooden cot in a pool of blood. Some of her clothes were missing and earrings and some other jewellery she was wearing, were also missing. Four used glasses were found nearby. Savitri's son Tejpal and his family stay in another house in the same village. He works as a medical practitioner. Following a complaint filed by him, an FIR against an unidentified person has been registered. The police suspect robbery to be one of the motives for the crime.

RWA members beat me up: Contractor

GREATER NOIDA: A private contractor hired for maintenance of Eldeco Green Meadows housing society in Sector Pi I has alleged that he was beaten up by some RWA members for not giving them Rs 5 lakh as commission in lieu of the contract given to him. The RWA, on the other hand, says the contractor has levelled false allegations as he has not been paid due to incomplete painting work in the society. On the complaint of contractor Mukesh Kumar, an FIR was lodged against five members of the RWA of Eldeco Green Meadows society following an order from the Surajpur court in the matter.

Work on Delhi-GZB-Meerut RRTS corridor to speed up

GHAZIABAD: A segment of Delhi-Ghaziabad-Meerut Regional Rapid Transit System (RRTS) corridor from Sahibabad to Duhai in Ghaziabad is likely to be made operational in March 2023. The National Capital Regional Corporation Transport (NCRTC) is working on a plan to achieve the target even though deadline for entire corridor is March 2024. With an intent to expedite work on the said segment the Uttar Pradesh chief secretary is likely to hold meeting on 29 April with all stakeholders including Ghaziabad Development Authority and Meerut Development

Authority and others. "There are three levels of monitoring or coordination committee that have been constituted to ensure that work on propose RRTS corridor takes place without any impediment and UP chief secretary in the capacity of the convener of one such committee has called a meeting which is likely to take place on 29 April" said an official. "This is to ensure that all problems coming in the way of corridor is addressed and solved without delay and this is in view of target set by government which wants first RRTS train operation on 17 Km route between Sahibabad to Duhai by March 2023 even

though the deadline for entire stretch is 2024" added the official. Speaking on the work progress the official said On 17 km stretch between Sahibabad to Duhai pre-construction work like road widening, tree cutting, geo-technical investigation, detailed designing and consultant for station design have also been appointed. The civil work on the said stretch will be taken up in two phases and civil engineering contract for it will be awarded soon, said the official. A GDA official meanwhile said that NCRTC needs land near Hindon Motel from where the proposed corridor is to pass.

Noida school fined Rs 5 lakh for not giving back 'excess' fee

NOIDA: The district fee regulation committee (DFRC) on Saturday imposed a fine of Rs 5 lakh on Apeejay School in Noida's Sector 16A for not complying with its February order of refunding the excess fees it charged for the last quarter of the 2018-19 academic session. The school has been given time till Tuesday to refund the excess fees and deposit the fine, failing which derecognition proceedings will be initiated. "Apeejay School had increased the fees mid-session in January 2019. It was asked to roll back the fee and a fine of Rs 1 lakh was also levied on it.

Man offered bottle of acid mistakes it for water, drinks it

GHAZIABAD: A 37-year-old software engineer out of job for the past four months allegedly killed his wife and three children by slitting their throats in their flat in Indirapuram on the intervening night of Saturday and Sunday. The alleged murder, however, came to light around 7pm on Sunday after the techie, Sumit Kumar, posted a video on the family's WhatsApp group and told the members that he had killed his wife and kids and would soon commit suicide. Police said Sumit had been jobless since December and the family was facing severe financial crisis

since then. He had joined a Bengaluru-based company — UST Global — in October last year but resigned two months later. His family, however, came to know about it during Holi in March, when he left Bengaluru permanently and started living with them in their Gyan Khand 4 flat. Sumit's wife Anshu Bala (32), who taught at Mother's Pride, sons Prathmesh (5) and Arav (4) and daughter Akriti (4), had been living in the 2BHK rented flat with the engineer's in-laws for the past two and a half years. Sumit's in-laws are currently in Bihar for a marriage function.

Noida private firm manager abducted from office, dumped on road

NOIDA: The manager of a software company was allegedly abducted at gunpoint by at least six assailants who barged into the office of Metro Info Solutions in Sector 63 on Friday. The gang allegedly pulled Paritosh Gaurav into a car and fled the spot after asking the owner of the firm to hand over Rs 10 lakh if they wanted to see him alive, the FIR said. Circle Officer II Piyush Singh, however, said the FIR was under scrutiny and the contents were being verified to ascertain the sequence of events.

GDA seeks time to acquire land for waste to energy plant

GHAZIABAD: It has been three months since NGT committee on solid waste management barred Ghaziabad Municipal Corporation(GMC) from dumping city's civic waste in Pratap Vihar dumping ground and since then GMC is struggling to dispose of its waste. The situation has reached a pass when GMC is forced to dump waste at any vacant plots as the situation spirals out of control. It is in this backdrop the district magistrate Ritu Maheshwari recently convened a meeting of Ghaziabad Development Authority(GDA) and GMC officials to find a permanent solution to the problem. "The GDA in the meeting has assured that by next week it will hand over remaining 18 acres of land out of total 36 cares in Galand where a waste-to-energy plant will be up" said Ritu Maheshwari, district magistrate. "We have been apprised by GDA that till date boundary wall on three sides of the spot have been erected and it will start work on approach road very soon" added Maheshwari.

दिव्यांग स्मार्ट कार्ड : डेढ़ साल में हो पाएं हैं मात्र 3 हजार रजिस्ट्रेशन

गाजियाबाद : दिव्यांगजन सशक्तिकरण के तहत बनाए जाए यनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड या दिव्यांग स्मार्ट कार्ड की प्रगति काफी सुस्त चल रही है। पिछले डेढ़ साल में मात्र 3 हजार दिव्यांग रमार्ट कार्ड के आवेदन आए हैं। शासन की तमाम कोशिशों के बाद भी दिव्यांग स्मार्ट कार्ड में तेजी आती नहीं दिख रही है। स्मार्ट कार्ड का काम अभी भी बहुत सुस्त रफ्तार से चल रहा है। दिव्यांग सशक्तिकरण अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बनाने का काम शुरु हुआ था। करीब डेढ़ साल पहले शुरु हुआ कार्ड बनाने

का काम काफी सुस्त रफ्तार से चल रहा है। इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है। गाजियाबाद जिले में 1,44,350 दिव्यांग रजिस्टर्ड हैं। वहीं डेढ साल में मात्र 3123 रजिस्ट्रेशन ही यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड के लिए हुए हैं। विभाग के तमाम प्रयासों के बाद भी कार्ड बनाने के काम में तेजी नहीं आ पाई है। इस संदर्भ में पूर्व में मुख्य सचिव अनूप कुमार पाण्डेय की ओर काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। दिव्यांग कल्याण अधिकारी रजनीश पाण्डेय ने बताया कि आईडी कार्ड के लिए दिव्यांगों को जागरुक किया जा रहा है।

मस्कुलोस्केलेटल इंजेक्शन थैरेपी पर दी जानकारी

गाजियाबाद : आइएएमआर संस्थान के फिजियोथैरेपी विभाग में मंगलवार को मस्कुलोस्केलेटल इंजेक्शन थेरेपी विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कनाडा से आए डा. सफदर सैयद अली ने मस्कूलोस्केलेटल इंजेक्शन थेरेपी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इंजेक्शन थैरेपी उपयोग करके मस्कुलोस्केलेटल समस्याओं का प्रभावी ढंग से उपचार किया जाता है। छात्रों के प्रश्नों के उत्तर मुख्य वक्ता ने दिए। विभागाध्यक्ष डा. शगुन अग्रवाल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आने वाली नई—नई तकनीकों के बारे में छात्रों को अपडेट होना चाहिए।

चोर क्रेन से उटा कर ले गए 22 लाख की बिजली केबिल

गाजियाबाद : विद्युत विभाग की गोविंदपुरम व संजय नगर दो साइट से भूमिगत केबिल के 10 ड्रम चोरी हो गए, जिन पर लिपटे करीब 2500 मीटर भूमिगत केबिल की कीमत करीब 22 लाख रुपये बताई जा रही है। नगर निगम से एनओसी न मिलने से पिछले एक माह से कार्य बंद था। आशंका है कि चोर ट्रक और क्रेन की मदद से केबिल ले गए। शहर के गोविंदपुरम विद्युत उपकेंद्र स्वर्ण जयंती पुरम व संजय नगर से कमला नेहरू नगर में जनवरी 2019 से 11 केवी भूमिगत विद्युत लाइन डालने का कार्य

चल रहा था। इसका कांट्रेक्ट मैसर्स राम नारायण गाजियाबाद को दिया गया था, जिसने भूमिगत केबिल के ड्रम विद्युत विभाग से उटाकर सड़क किनारे साइड में रखे हुए थे। नगर निगम से अनुमति न मिलने के कारण 20 मार्च से दोनों साइट पर काम बंद था, लेकिन केबिल के ड्रम साइट पर ही पड़े थे, जिन पर करीब 2500 मीटर केबिल लिपटा हुआ था। गोविंदपुरम विद्युत उपकेंद्र के अवर अभियंता अनुराग गुप्ता ने थाना कविनगर में लिखित शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दिल्ली समेत कई रेलवे स्टेशनों को बम से उडाने की धमकी, स्टेशन मास्टर

को भेजा लेटर

दिल्ली: शामली रेलवे स्टेशन समेत दिल्ली, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर आदि स्टेशनों को 13 मई को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ऐसा न होने पर 16 मई को काशी विश्वनाथ मंदिर, दिल्ली आदि प्रमुख मंदिरों को उडाने की धमकी भरा पत्र डाक के द्वारा शामली स्टेशन मास्टर को भेजा गया है। लेटर पर पेन से लिखा गया है, हेंड राइटिंग काफी खराब है, जिसके कारण उसे पढ़ना काफी मुश्किल हो रहा है। इसे जैश मोहम्मद के नाम से भेजा गया है। लेटर को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

स्टेशन उड़ाने की धमकी को जिले में अलर्ट

गाजियाबाद : रेलवे स्टेशन को बम से उडाने की धमकी को लेकर जिले में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। स्टेशन के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में पुलिस ने चेकिंग बढा दी गई है। सिविल पुलिस और रेलवे पुलिस की टीमों ने मिलकर देर रात तक चेकिंग की। एसपी सिटी श्लोक कुमार ने बताया कि आतंकी धमकी को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जीआरपी और आरपीएफ के साथ कोआर्डिनेशन कर रेलवे स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों में चेकिंग कराई जा रही है। सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया है। थाना प्रभारियों को निरंतर चेकिंग



करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में जिन भी थानाक्षेत्रों में रेलवे स्टेशन या हॉल्ट पड़ रहा है उन्हें विशेष निर्देश दिए गए हैं। नगर कोतवाली, विजयनगर, कविनगर

वसुंधरा : फीस वृद्धि के विरोध में

व लोनी समेत अन्य थानों के प्रभारियों से कहा गया है कि वे रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक के आसपास निरंतर गस्त कराएं। रात और पीक आवर्स में खुद भी निरीक्षण करते रहें।

जयपुरिया स्कूल में बच्चों को प्रवेश देने का आदेश

आशा कार्यकर्ताओं पर होगी 15 माह तक शिश् की देखभाल की जिम्मेदारी

गाजियाबाद : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नवजात शिशु मृत्यु दर पर अकुंश लगाने के लिए होम बेस्ड न्यू बोर्न केयर (एचबीएनसी) कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा। नए कार्यक्रम के मुताबिक आशा कार्यकर्ताओं को प्रसव के 42 दिन तक नवजात और माता की देखभाल करनी होती है। आशाओं को शिशुओं की देखभाल हेतु हर तीन माह के अंतराल पर उनके घर जाकर देखना होगा। शिशु की आयु 15 माह होने तक आशा को गृह भ्रमण करके उसके स्वास्थ्य से संबंधित हर पहलू की निगरानी करनी होगी।

कड़ी सुरक्षा में ईवीएम का होगा मूवमेंट

गाजियाबाद : कमतगणना के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इवीएम का मूवमेंट होगा। इसके लिए प्रशासन द्वारा प्लान तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय सुरक्षाबलों के पहरे में इवीएम स्ट्रांग रूम से मतगणना स्थल तक पहुंचाई जाएंगी। इसके लिए स्ट्रांग रूम से लेकर मतगणना स्थल तक बेरीकेडिंग बनाई जाएंगी। बेरीकेडिंग की इस गैलरी से होकर ही इवीएम मतगणना स्थल तक पहुंचेंगी। बता दें कि जिले में पांच विधानसभा क्षेत्रों लोनी, साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर, मुरादनगर की मतगणना होनी हैं। इन सभी विध गानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए अलग-अलग पंडाल बनाए जाएंगे। सभी विधानसभा क्षेत्रों की इवीएम भी अलग-अलग स्ट्रांग

रूम में रखी गई हैं। **BUREAU OFFICE**

Bureau Chief 12/516, Friends Co-operative Society Vasundhra, Ghaziabad (UP) Mobile: +91 8130640077 Email: vikram@tbcgzb.com www.tbcgzb.com

VIKRAM KUMAR

Contact for Press Release and Advertisements

लगातार प्रदर्शन कर रहे वसुंधरा के जयपुरिया स्कूल के अभिभावकों को मंगलवार को फौरी राहत मिल गई। जिला विद्यालय निरीक्षक पंकज पांडे ने एक आदेश जारी करते हुए जयपुरिया स्कूल प्रबंधन को फीस न जमा करने वाले सभी छात्रों को प्रवेश देने का आदेश दिया है। कोर्ट का निर्णय आने तक बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके चलके यह निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए स्कूल को दो दिन का समय दिया गया है। हालांकि अभिभावक संघ का कहना है कि स्कूल प्रबंधन अभिभावकों के साथ वार्ता को तैयार ही नहीं



जिला विद्यालय निरीक्षक ने सोमवार की शाम सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल को नोटिस जारी कर बच्चों को प्रवेश देने को कहा है। स्कूल प्रबंधन ने नोटिस न मिलने की बात कही थी। जिससे नाराज अभिभावक मंगलवार को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पहुंचे। वहां जाकर बच्चों व अभिभवकों ने स्कूल को जारी नोटिस की कॉपी ली और दोपहर को स्कूल पहुंचकर प्रबंधन को मुहैया करवाई। स्कूल को दिए

आदेश में जिला विद्यालय निरीक्षक

BUREAU OFFICE PRATEEK BHARGAVA

Bureau Chief 5, Ashok Vihar, 3rd Floor, GMS Road, Nr. Ballupur Chowk, Dehradun. Mobile: +91 8130640011 Email: prateekb@tbcgzb.com www.tbcazb.com

Contact for Press Release and Advertisements

ने कहा है कि उच्च न्यायालय के आदेशों का विद्यालय को पालन करना होगा। उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय आने तक फीस न देने वाले छात्रों की टीसी न निर्गत की जाए। इतना ही नहीं यह भी निर्देश दिए गए हैं कि छात्रों का स्कूल में प्रवेश न रोका जाए। न्यायालय का अंतिम निर्णय आने के बाद आगे की कार्रवाई करे। स्कूल की प्रधानाचार्य मंजू राणा ने साफ कर दिया कि फीस न जमा करने वाले बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश का जवाब तैयार किया जा रहा है। बुधवार तक इसका जवाब दे दिया

Printed and Published by Dheeraj Kumar Bhargav at B.F.L Inrotech Ltd, C-9, Sector-3 Noida, Distt. Gautam Budh Nagar and Published at 282, Sarai Nazar Ali, behind MMG Hospital Ghaziabad (U.P.) 201 001. Editor: Dheeraj Kumar, Resident Editor: Manisha Bhargava** Email: editor@tbam.co.in (RNI. No): UPBIL / 2009 / 28691 Postal Registration No. UP/GBD-80/2016- 18. Advertisement: Ph. No.: 0120-2850800, 2850297, Fax: 0120-4561000 at 67, 1st Floor, Richpal Puri, Hapur Road, Ghaziabad (U.P.)** Responsible for selection of News under the PRB Act. Reproduction in any manner, electronic or otherwise in whole or in post without prior written permission is prohibited.

हो रहा है। बाल संरक्षण आयोग

के पत्र को संज्ञान में लेते हुए,